structions issued after the inspection was not found satisfactory, RBI has taken up another inspection in 1995 with reference to Company's financial position as on 31.3.1995. On completion of the examination of the findings of the inspection, action, as appropriate, will be taken by RBI under the powers vested in it.

हेरोइन की तस्करी

1294. **श्री इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेशों से भारत में हेरोइन की तस्करी बढ़ने का ब्यौरा क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी हेरोइन जब्त की गई;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से भारत में हेरोइन की तस्करी बढ़ने का ब्यौरा क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी हेरोइन जब्त की गई;

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) स्वापक औषध अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया हैं अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह बढ़ रही हैं अथवा नहीं। तथापि पश्चिम में गोल्डन क्रिसेन्ट (पाकिस्तान, अफगानिलस्तान, ईरान) तथा पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमाल रथा-इलैंड-लाओस) की निकटता के कारण भारत हेरोइन अवैध व्यापार के लिए संवेदनशीन हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान हेरोइन की जब्त की गई कुल भाग क्रमश: 1088 कि.ग्रा. 1011 कि.ग्रा. और 1543 कि.ग्रा. (अनंतिम) थी।

(ग) सभी प्रर्वतन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्याधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई हैं। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं, को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

हेरोइन बनाने के एक प्रारंभिक रसायन एसोटिक एन्हाइड्राइड को एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया हैं तथा एसेटिक एनहाइड्राइड के निर्माण वितरण विक्रय आयात, निर्यात तथा उपभोग के विनियमन करने के लिए विनियमन आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीमा शुल्क एक्ट के अंतर्गत भारत-पाक सीमा के 50 कि.मी. तथा भारत-म्यांमार सीमा के 100 कि.मी. के भीतर रसायन के संचलन को नियंत्रित किया गया हैं।

Formation of Interim Insurance Regulatory Authority

1295. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether an Interim Insurance Regulatory Authority has been formed; and

(b) if so, the major objectives of forming the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Interim Insurance Regulatory Authority (IIRA) was set up under the overall control of the Finance Ministry, as a precursor to the proposed statutory regulatory authority under a resolution issued by the Government on 23rd January, 1996. The Chairman of the IIRA will exercise the powers presently vested with the Controller of Insurance (COI). The IIRA will assist the Government in preparing a comprehensive legislation for ensuring healthy regulation, promotion and orderly growth of the insurance market and exercise such other non-statutory functions as may be assigned to it by the Central Government from time to time.

कटे-फटे तथा उपयोग में न लाए जा सकने योग्य करेंसी नोट

1296. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान वर्ष-वार देश में कटे-फटे एवं उपयोग में न लाए जा

सकने योग्य विभिन्न मूल्य के कितने करेंसी नोट राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को भेज गए;

(ख) इन में विभिन्न मूल्य के कितने करेंसी नोट प्रतिवर्ष नष्ट किए गए तथा कितने पुनः प्रचालिन के लिए वापस किए गए

(ग) रद्द किए गए, सड़े-गले और कटे-फटे करेंसी नोटों को न बदलने तथा नए नोटों के पर्याप्त संख्या में जारी न करने के क्या कारण हैं; और.

(घ) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक के पास नष्ट करने के लिए जमा करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवीप्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पर्याप्त संसाधन जटाए जाने हेतु सुझाव

1297. **श्री अजीत जोगी** :

श्री एस. एस. सूरजेवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या 1995-96 के आर्थिक सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने हेतु सुझाव दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/ अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबीप्रसाद पाल) : (क) से (ग) संसाधनों की सख्त तंगी के बावजूद सरकार पिछले तीन बजटों में सामाजिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय पूल आवंटनों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में काफी अधिक वृद्वि की हैं। सामाजिक क्षेत्रों के लिए उच्चतर बजटीय आवंटनों की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 की आर्थिक समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया हैं कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा उपयुक्त संसाधन जुटाने होंगे।

विद्युत नीति के विरूद्व विरोध

1298. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की वर्तमान विद्युत नीति के विरूद्व अपना विरोध दर्ज किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विद्युत नीति में कतिपय परिवर्तन करने का विचार रखती हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विद्युत नीति में कतिपय परिवर्तन करने का विचार रखती हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; औश्र

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Clearance of Hypothecation Accounts by PNB

1299. SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether PNB, Zonal Office in Calcutta has not yet sorted out the issues pertaining to clearance of hypothecation accounts of various vehicle owners;

(b) whether in the case of some of the vehicle owners even after clearing their dues to the bank, prolonged litigations are still going on; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) Punjab National Bank (PNB) has reported that as per available records, no such issue pertaining to clearance of hypothecation accounts of various vehicle owners, is pending in the Zonal Office of the Bank at Calcutta.

(b) PNB has also reported that there is no such case reported to the bank where prolonged litigation is continuing even after dues to the bank are cleared.

(c) The bank has, however, mentioned that in one loan account in a branch at Calcutta, a suit was filed for non payment of dues. In the account, during the pendency of the suit, a compromise offered by third party was accepted in terms of which waivement of interest was